

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

मोहला- मानपुर में ग्रामीण विकास का अध्ययन

नुतन कुमार भुआर्य

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर

सतीश कुमार

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़

सारांश

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण विकास ही देश की प्रगति का आधार है। छत्तीसगढ़ का मोहला-मानपुर विकासखण्ड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ कृषि, वनोपज, लघु उद्योग और सरकारी योजनाएँ ही आजीविका के प्रमुख साधन हैं। यहाँ के लोग परंपरागत जीवनशैली पर आश्रित हैं तथा गरीबी, बेरोजगारी और प्रवास जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस शोधपत्र का उद्देश्य मोहला-मानपुर विकासखण्ड में ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभाव देखना, आजीविका के पारंपरिक और नवीन स्रोतों की पहचान करना तथा भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

1. प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ग्रामीण विकास एक केंद्रीय विषय है। यहाँ की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण विकास के बिना भारत की प्रगति अधूरी है। ग्रामीण विकास का संबंध केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढाँचा, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संरक्षण और सांस्कृतिक उत्थान इन सभी में निहित है।

छत्तीसगढ़ राज्य, जो प्राकृतिक संसाधनों और वनों से समृद्ध है, इससे ग्रामीण विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ राज्य का एक नवगठित जिला है, जिसका गठन 2 सितंबर 2022 को राजनांदगांव जिले से पृथक करके किया गया है। यह जिला दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय मोहला है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है और कांकेर व बालोद जिले के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य से भी सीमाएं साझा करता है।

मोहला-मानपुर विकासखण्ड इस संदर्भ में अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी आदिवासी है, जो आज भी परंपरागत जीवनशैली और जीविकोपार्जन के साधनों पर निर्भर है। कृषि और वनोपज यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ परंपरागत जीवनशैली, सामाजिक संरचना और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन योजनाओं का लाभ पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। इस कारण गरीबी, बेरोजगारी और प्रवास जैसी समस्याएँ यहाँ अधिक देखने को मिलती हैं।

2. पूर्व शोध समीक्षा

1. पी. सी. महालनोबिस (1955) महालनोबिस ने भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को आधार बनाकर आत्मनिर्भरता की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका मत था कि केवल शहरी औद्योगीकरण ग्रामीण गरीबी दूर करने में पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सिंचाई एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने, सहकारी संस्थाओं के विस्तार तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देकर ही ग्रामीण भारत को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। महालनोबिस का मॉडल संतुलित विकास का पक्षधर था, जिसमें ग्रामीण समाज को योजनाओं के केंद्र में रखा गया।

2. रॉबर्ट चेम्बर्स (2002) चेम्बर्स ने *Participatory Rural Appraisal (PRA)* के विचार को और आगे बढ़ाते हुए “लोगों द्वारा संचालित विकास” पर जोर दिया। उनका कहना था कि ग्रामीण विकास की किसी भी योजना का वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब स्थानीय समुदाय योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। उन्होंने तकनीकी साधनों, सामुदायिक भागीदारी और महिला SHGs को ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत आधार माना।

3. डी. आर. गाडगिल (1971) गाडगिल ने ग्रामीण विकास को संतुलित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से समझाया। उनके अनुसार, यदि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाएगी तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाना, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर निवेश बढ़ाना ही ग्रामीण विकास की कुंजी है। गाडगिल का मानना था कि योजना आयोग और सरकार को ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का वितरण करना चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम हो सके।

4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2010) UNDP ने ग्रामीण विकास को “सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)” से जोड़ते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जल-स्वच्छता ग्रामीण जीवन को बदलने के मुख्य आयाम हैं। 2015 के बाद SDGs के लागू होने पर UNDP ने विशेष रूप से यह बताया कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास की दिशा में प्रयास न किए गए, तो वैश्विक विकास अधूरा रहेगा।

5. रमेश चंद्र (2017) भारतीय अर्थशास्त्री रमेश चंद्र ने ग्रामीण भारत में विकास की रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार ग्रामीण विकास केवल कृषि सुधारों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें ग्रामीण उद्योग, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और बाज़ार से बेहतर संपर्क शामिल होना चाहिए। उन्होंने “Doubling Farmers’ Income by 2022” रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

3. शोध के उद्देश्य

इस शोधपत्र का उद्देश्य मोहला-मानपुर विकासखण्ड की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए ग्रामीण विकास के लिए चल रही योजनाओं, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

- मोहला-मानपुर विकासखण्ड में ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
- ग्रामीण युवाओं की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करना।
- कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- रोजगार और आजीविका के प्रमुख स्रोतों की पहचान करना।
- महिला एवं स्व-सहायता समूहों की भूमिका समझना।
- भविष्य की संभावनाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- नीति-निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध परिकल्पना एवं तर्क

1. कृषि एवं वनोपज

- **परिकल्पना:** मोहला-मानपुर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और वनोपज है, किंतु पारंपरिक खेती और विपणन की कमजोरी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **तर्क:** अधिकांश ग्रामीण किसान वर्षा-आधारित खेती करते हैं और उत्पादन में आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं हो पाता। वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, शहद और चिरौंजी की प्रचुरता होने के बावजूद इनके प्रसंस्करण व विपणन की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को कम लाभ मिलता है।

2. सरकारी योजनाएँ

- **परिकल्पना:** मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कौशल विकास योजनाएँ ग्रामीण जीवन सुधारने में सहायक रही हैं, लेकिन क्रियान्वयन की कमियों के कारण उनका प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया।
- **तर्क:** ग्रामीणों को मनरेगा से आंशिक रोजगार मिला है, सड़क योजना से संपर्क बढ़ा है और SHG को प्रोत्साहन मिला है। परंतु कई बार योजनाओं का लाभ बिचौलियों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विलंब के कारण पूरी तरह से ग्रामीण समाज तक नहीं पहुँच पाता।

3. महिला स्व-सहायता समूह (SHGs)

- **परिकल्पना:** महिला SHGs ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है।
- **तर्क:** स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ ऋण प्राप्त कर छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन व किराना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।

4. रोजगार एवं प्रवास

- **परिकल्पना:** रोजगार के सीमित अवसरों और कौशल विकास की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं का बाहरी राज्यों की ओर प्रवास अधिक है।
- **तर्क:** स्थानीय स्तर पर उद्योग व सेवाक्षेत्र विकसित न होने से युवा मजदूरी और रोजगार की तलाश में शहरों और अन्य राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली) की ओर प्रवास करते हैं। यह प्रवास परिवारों की आय बढ़ाता है, लेकिन सामाजिक-पारिवारिक असंतुलन भी उत्पन्न करता है।

5. सामाजिक-आर्थिक स्थिति

- **परिकल्पना:** शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना के स्तर में सुधार से ग्रामीण जीवन में स्थायी विकास की संभावना है।

- **तर्क:** साक्षरता दर में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवनशैली में परिवर्तन आ रहा है। यदि इन क्षेत्रों को और मजबूत किया जाए तो गरीबी व अशिक्षा की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

6. ग्रामीण विकास की संभावनाएँ

- **परिकल्पना:** कृषि आधुनिकीकरण, वनोपज प्रसंस्करण, लघु उद्योग और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए तो मोहला-मानपुर क्षेत्र सतत एवं समावेशी विकास का मॉडल बन सकता है।
- **तर्क:** इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। यदि कृषि में उन्नत तकनीक, सिंचाई साधन और आधुनिक विपणन प्रणाली लाई जाए तथा वनोपज आधारित उद्योग स्थापित किए जाएँ, तो क्षेत्र आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। साथ ही कौशल विकास और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे।

5. शोध की आवश्यकता और महत्व

मोहला-मानपुर विकासखण्ड मुख्यतः कृषि और वनोपज पर आधारित क्षेत्र है, जहाँ जीवन-स्तर अभी भी पिछड़ेपन, गरीबी, सीमित रोजगार और प्रवास जैसी समस्याओं से प्रभावित है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त विकास नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास पर शोध करना आवश्यक है ताकि स्थानीय चुनौतियों और अवसरों की पहचान कर भविष्य की योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

इस शोध का महत्व इसलिए है क्योंकि यह न केवल कृषि, वनोपज और महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका को स्पष्ट करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन भी करता है। इसके निष्कर्ष नीति-निर्माताओं और प्रशासन को रोजगार सृजन, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में व्यावहारिक सुझाव दे सकते हैं। साथ ही यह अध्ययन स्थानीय समाज को भी अपनी समस्याओं को समझने और समाधान में सक्रिय भागीदारी निभाने की प्रेरणा देता है।

6. शोध पद्धति

इस शोधपत्र में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है।

- **प्राथमिक स्रोत:** क्षेत्रीय अवलोकन, ग्रामीणों से अनौपचारिक चर्चा।
- **द्वितीयक स्रोत:** (जनगणना रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट, विभिन्न शोधपत्रों एवं पुस्तकों) का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मोहला-मानपुर क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है।

7. सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

मोहला-मानपुर विकासखण्ड छत्तीसगढ़ राज्य के मोहला-मानपुर अ.चौकी जिले का एक आदिवासी बहुल और वनाच्छादित क्षेत्र है। यह इलाका भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जीवन जंगलों, कृषि और पारंपरिक गतिविधियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग दस लाख है, जिसमें अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यहाँ लिंगानुपात संतुलित है और प्रति एक हजार पुरुषों पर लगभग 1027 महिलाएँ हैं, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

शिक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र की साक्षरता दर कुल 65.7% (पुरुष 74.4%, महिलाएँ 57.27%) है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, फिर भी महिला शिक्षा अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। यहाँ गोंड, हल्बा, आदिवासी समुदाय प्रमुख रूप से निवास करते हैं, इन समुदायों की अपनी विशिष्ट परंपराएँ, रीति-रिवाज और संस्कृति है। छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोलियाँ यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हैं और लोक नृत्य, त्योहार, मेलों तथा प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है।

आर्थिक दृष्टि से मोहला-मानपुर क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि और वनोपज पर निर्भर है। अधिकांश लोग वर्षा आधारित खेती करते हैं और धान, मक्का, कोदो, कुटकी जैसी फसलें उगाते हैं। इसके अतिरिक्त महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौंजी और शहद जैसी वनोपज ग्रामीणों की नकद आय के प्रमुख स्रोत हैं। कृषि और वनोपज के अतिरिक्त मजदूरी तथा प्रवास भी यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दुर्ग, रायपुर, भिलाई और महाराष्ट्र के औद्योगिक शहरों की ओर पलायन करते हैं। सामाजिक दृष्टि से यहाँ का जीवन सामूहिकता और सहयोग पर आधारित है। ग्रामीण समाज में परंपरागत जीवनशैली और आदिवासी संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। परिवार और समुदाय मिलकर त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत रहते हैं। यद्यपि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और शिक्षा का निम्न स्तर जैसी समस्याएँ यहाँ मौजूद हैं, फिर भी यह क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है।

8. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

मोहला-मानपुर विकासखण्ड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। यहाँ की अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। धान इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और खरीफ मौसम में अधिकांश खेत धान से आच्छादित रहते हैं। इसके अलावा मक्का, कोदो, कुटकी जैसी मोटा अनाज (मिलेट्स) तथा अरहर, उड़द, मूंग और चना

जैसी दलहनी फसलें भी यहाँ बोई जाती हैं। सरसों, तिल और मूंगफली जैसे तेलहन भी कुछ हिस्सों में उगाए जाते हैं। खेती मुख्यतः पारंपरिक पद्धतियों से की जाती है और यह अभी भी वर्षा पर आश्रित है। नलकूप, कुएँ और तालाब जैसी सिंचाई की स्थानीय व्यवस्थाएँ तो मौजूद हैं, किंतु बड़े पैमाने पर नहर सिंचाई या आधुनिक साधनों की कमी के कारण उत्पादन सीमित है।

खेती की प्रकृति छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। खेतों का आकार छोटा होने के कारण किसान बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते। यही कारण है कि यहाँ कृषि अधिकतर आत्मनिर्भरता के लिए की जाती है और बाजार में बेचने योग्य अधिशेष फसलें अपेक्षाकृत कम होती हैं। पारंपरिक बीज और बैल-हल का प्रयोग अभी भी कई स्थानों पर प्रचलित है, हालांकि धीरे-धीरे ट्रैक्टर, उन्नत बीज और उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा है। विपणन और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी उपज बिचौलियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि तक सीमित नहीं है। वनोपज इस क्षेत्र की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत है। महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौजी, हर्षा, बहेरा, आंवला और शहद जैसे उत्पाद ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें से तेंदूपत्ता और महुआ नकद आय के सबसे बड़े स्रोत हैं। ग्रामीण परिवार इन वनोपजों को इकट्ठा कर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं, किंतु उचित मूल्य की कमी और बिचौलियों का दबदबा उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाए रखता है। यदि वनोपज का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर किया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है।

मजदूरी और प्रवास भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। जिन परिवारों के पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है, वे दिहाड़ी मजदूरी या मनरेगा जैसी योजनाओं पर आश्रित रहते हैं। स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दुर्ग, रायपुर, भिलाई और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में पलायन करते हैं। प्रवास से कुछ हद तक आय में वृद्धि होती है, लेकिन इसके कारण परिवार की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना प्रभावित होती है।

इस प्रकार मोहला-मानपुर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुआयामी है, जिसमें कृषि, वनोपज, पशुपालन, मजदूरी और प्रवास सभी शामिल हैं। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होने के बावजूद आधुनिक तकनीक, सिंचाई, विपणन और प्रसंस्करण उद्योगों के अभाव में ग्रामीणों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। यदि कृषि को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया जाए, वनोपज पर आधारित उद्योग स्थापित हों और ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो यह क्षेत्र आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है।

9. सरकारी योजनाएँ और कौशल विकास

मोहला-मानपुर विकासखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ लागू की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), जिसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों के लिए अस्थायी आजीविका का साधन बनी है। यद्यपि इसमें रोजगार स्थायी नहीं है, फिर भी आर्थिक कठिनाइयों के समय यह योजना बड़ी सहायता सिद्ध होती है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह (SHGs) का गठन किया गया है। ये समूह महुआ संग्रहण, तेंदूपत्ता तोड़ाई, सब्जी उत्पादन, बुनाई और हस्तशिल्प जैसे कार्यों में सक्रिय हैं। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने मोहला-मानपुर क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। पहले जहाँ कई गाँव मुख्य मार्गों से कटे हुए थे, वहीं अब सड़क नेटवर्क के विस्तार से बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाना आसान हो गया है। इससे कृषि और वनोपज उत्पादों की बिक्री में भी सुविधा हुई है।

स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया है। इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे ग्रामीणों में स्वास्थ्य और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता आई है। इसी प्रकार मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं ने बच्चों के पोषण और शिक्षा स्तर को सुधारने में मदद की है।

युवाओं के लिए कौशल विकास की दिशा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) महत्वपूर्ण रही है। इस योजना के तहत युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा, बिजली मिस्त्री, मोबाइल रिपेयरिंग, कृषि यंत्र संचालन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालाँकि स्थानीय स्तर पर उद्योगों की कमी के कारण प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर सीमित हैं, फिर भी यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहला-मानपुर में सरकारी योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी है। इनसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी योजनाओं का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है और क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा निरंतरता की कमी है। यदि इन योजनाओं को स्थानीय उद्योग और संसाधनों से जोड़ा जाए तो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया और अधिक तेज एवं स्थायी हो सकती है।

10. रोजगार, प्रवास एवं चुनौतियाँ

मोहला-मानपुर विकासखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर मुख्यतः कृषि और वनोपज पर आधारित हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी धान, मक्का, कोदो-कुटकी जैसी फसलों की खेती में संलग्न है, किंतु यह खेती वर्षा पर निर्भर और मौसमी है। इसके अतिरिक्त महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौजी और शहद जैसी वनोपज ग्रामीणों की नकद

आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पशुपालन और मुर्गीपालन भी अतिरिक्त आय का साधन है। मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों को अस्थायी रोजगार प्रदान किया है, जबकि महिला स्व-सहायता समूहों ने हस्तशिल्प, बुनाई और सब्जी उत्पादन जैसे स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके बावजूद स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार की कमी बनी हुई है।

स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उद्योग और उत्पादन इकाइयों न होने के कारण यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर प्रवास करने को विवश होते हैं। काम की तलाश में ग्रामीण दुर्ग, भिलाई, रायपुर और महाराष्ट्र के औद्योगिक शहरों में पलायन करते हैं, जहाँ वे प्रायः असंगठित मजदूरी जैसे ईंट-भट्टा, निर्माण कार्य और फैक्ट्री मजदूरी करते हैं। प्रवास से परिवार की नकद आय तो बढ़ती है, लेकिन इससे कई सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। घर पर महिलाएँ और बुजुर्ग अधिक बोझ उठाते हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और पारिवारिक जीवन में असंतुलन पैदा होता है।

इन परिस्थितियों से जुड़ी कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई साधनों, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीक की कमी उत्पादन को सीमित रखती है। रोजगार के अवसर सीमित होने से लोग मजबूरन प्रवास करते हैं। कौशल और तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण ग्रामीण लोग केवल दिहाड़ी मजदूरी तक सीमित रहते हैं। विपणन और प्रसंस्करण उद्योगों की अनुपस्थिति से स्थानीय उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके साथ ही गरीबी, सामाजिक असमानता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएँ भी ग्रामीण विकास में बाधा बनती हैं। यदि यहाँ स्थानीय स्तर पर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, वनोपज आधारित उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और प्रवास की समस्या भी कम हो सकती है।

11. ग्रामीण विकास की संभावनाएँ

मोहला-मानपुर विकासखण्ड प्राकृतिक संसाधनों, वन सम्पदा और कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीण जीवन में विकास की अनेक संभावनाएँ विद्यमान हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र धान और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त है। यदि यहाँ आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई के साधन और वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई जाएँ तो उत्पादन और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही कृषि प्रसंस्करण इकाइयों जैसे धान मिल, कोदो-कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट और तेल मिल स्थापित करने से स्थानीय स्तर पर उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

वनोपज के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ हैं। महुआ, तेंदूपत्ता, चिरौंजी, हर्षा, आंवला और शहद जैसे उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया जाए तो ग्रामीणों को अधिक लाभ मिल सकता है। यदि इन वनोपजों पर आधारित लघु उद्योग स्थापित हों तो यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकता है। इसी प्रकार बांस और लकड़ी पर आधारित हस्तशिल्प एवं फर्नीचर उद्योग भी ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।

महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण विकास की संभावनाएँ और भी बढ़ जाती हैं। ये समूह सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मसाला उत्पादन, शहद पैकेजिंग और सब्जी उत्पादन जैसे छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं बल्कि पूरे परिवार की आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही, इन्हें सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं से बेहतर तरीके से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

शिक्षा और कौशल विकास भी ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। यदि युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, बिजली मिल्की, कृषि यंत्र संचालन जैसे कौशल प्रदान किए जाएँ और इन्हें स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाए तो स्थायी रोजगार का आधार तैयार हो सकता है। इससे प्रवास की समस्या भी काफी हद तक कम होगी।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ संभावनाएँ हैं। पहाड़ी भू-भाग, जंगल और आदिवासी संस्कृति इस क्षेत्र को विशेष पहचान देते हैं। यदि इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो यह ग्रामीणों के लिए नए रोजगार का साधन बन सकता है।

कुल मिलाकर मोहला-मानपुर विकासखण्ड में ग्रामीण विकास की संभावनाएँ अत्यधिक हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना, महिला स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाओं का विस्तार तथा पर्यटन को बढ़ावा देकर यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाया जा सकता है।

12. चर्चा और विश्लेषण

मोहला-मानपुर विकासखण्ड का अध्ययन यह दर्शाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और वनोपज पर आधारित है। धान, मक्का और कोदो-कुटकी जैसी फसलें आजीविका का आधार हैं, किंतु उत्पादन पद्धतियों की पारंपरिकता और विपणन की कमी से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। पशुपालन और वनोपज संग्रहण ने ग्रामीण जीवन को सहारा दिया है, परंतु आय का स्तर अभी भी सीमित है।

सरकारी योजनाओं से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। मनरेगा ने आंशिक रोजगार दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने संपर्क सुधारा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त किया। फिर भी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। परंतु संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा। योजनाओं के प्रभाव में असमानता है। कृषि और वनोपज की क्षमता अधिक है, लेकिन विपणन, तकनीक और आधारभूत संरचना कमजोर है। कौशल विकास योजनाएँ उपयोगी हैं, परंतु उद्योगों का अभाव युवाओं को प्रवास के लिए विवश करता है। मोहला-मानपुर संसाधन सम्पन्न क्षेत्र है लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा।

- कृषि पर वर्षा निर्भरता।
- वनोपज में बिचौलियों की दखल।
- कौशल विकास योजनाएँ उपयोगी हैं पर रोजगार की स्थिरता नहीं।
- महिला समूहों ने बदलाव की दिशा दिखाई है।

13. निष्कर्ष

मोहला-मानपुर विकासखण्ड का अध्ययन यह दर्शाता है कि यहाँ ग्रामीण जीवन का आधार कृषि और वनोपज है, किंतु पारंपरिक पद्धतियों, सीमित संसाधनों और बाजार तक पहुँच की कमी के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है। सरकारी योजनाओं ने अवश्य रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में सुधार की दिशा दी है, विशेषकर स्व-सहायता समूहों ने ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित की है।

फिर भी इस क्षेत्र में रोजगार की कमी, प्रवास की समस्या और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इस शोध से स्पष्ट है कि यदि कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, वनोपज का मूल्य संवर्धन कर स्थानीय उद्योग स्थापित हों, महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाए और स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं का विस्तार हो, तो मोहला-मानपुर सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बन सकता है।

14. सुझाव (Recommendations)

1. कृषि का आधुनिकीकरण

मोहला-मानपुर क्षेत्र के ग्रामीण विकास के लिए कृषि का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। वर्तमान में खेती मुख्यतः पारंपरिक पद्धतियों और वर्षा पर आधारित है, जिसके कारण उत्पादन स्तर कम रहता है। यदि कृषि को आधुनिक तकनीकों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक एवं जैविक खादों का संतुलित उपयोग, सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रींकलर पद्धति, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा डिजिटल कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तो उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। साथ ही, किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी, प्रशिक्षण और बाजार तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वे अपनी फसलों को उचित मूल्य पर बेच सकें। वनोपज और नकदी फसलों के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना भी जरूरी है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। अतः कृषि का आधुनिकीकरण मोहला-मानपुर के सतत और समावेशी ग्रामीण विकास की आधारशिला सिद्ध हो सकता है।

2. वनोपज का मूल्य संवर्धन

मोहला-मानपुर क्षेत्र में वनोपज ग्रामीणों की आय और जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। तेंदूपत्ता, महुआ, चिरौंजी, शहद, हर्षा-बहेड़ा तथा लघु वनोपज जैसी वस्तुएँ यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु इनका संग्रहण और विक्रय प्रायः कच्चे रूप में ही किया जाता है। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को इनके वास्तविक मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता और बिचौलिए अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। यदि वनोपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाए तो इसका मूल्य संवर्धन संभव है और ग्रामीणों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके लिए छोटे-छोटे वनोपज आधारित उद्योगों, सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही, बाजार तक सीधी पहुँच और ई-मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादों की बिक्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सकता है। इस प्रकार वनोपज का मूल्य संवर्धन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

3. स्थायी रोजगार के अवसर

मोहला-मानपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की अस्थिरता और प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति है। वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि, वनोपज संग्रहण और मनरेगा जैसे अस्थायी रोजगारों पर निर्भर है, जिससे उनकी आय सीमित और असुरक्षित रहती है। इस स्थिति में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करना ग्रामीण विकास की अनिवार्य शर्त है। इसके लिए सबसे पहले स्थानीय स्तर पर लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और वनोपज आधारित इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, ग्रामीण पर्यटन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन और बांस-आधारित शिल्प जैसे विकल्प भी स्थायी रोजगार के सशक्त साधन हो सकते हैं। यदि प्रशासन और समाज मिलकर इस दिशा में ठोस पहल करें तो प्रवास की समस्या कम होगी और ग्रामीणों को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक व स्थायी आजीविका उपलब्ध होगी।

4. महिला स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहला-मानपुर क्षेत्र में अनेक SHGs सक्रिय हैं, जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया है। परंतु इनके सामने पूँजी की कमी, बाजार तक सीमित पहुँच और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता जैसी

चुनौतियाँ मौजूद हैं। यदि SHGs को आसान ऋण सुविधा, विपणन नेटवर्क और आधुनिक उद्यमिता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो वे अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही, इनके माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, बांस उत्पाद, डेयरी, पोल्ट्री और वनोपज आधारित लघु उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि समाज में उनकी सामाजिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार महिला स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण मोहला-मानपुर के समग्र ग्रामीण विकास के लिए एक स्थायी आधार बन सकता है।

5. कौशल विकास और शिक्षा

ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा और कौशल विकास को आधारभूत स्तंभ माना जाता है। मोहला-मानपुर क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अभी भी कमी है। अनेक युवा उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिसके कारण वे आधुनिक रोजगार के अवसरों से नहीं जुड़ पाते। यदि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ तो बच्चों और युवाओं को आधुनिक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होगा। साथ ही, आईटी, डिजिटल साक्षरता, कृषि-आधारित तकनीक और लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। शिक्षा और कौशल विकास का यह समन्वय मोहला-मानपुर के युवाओं को रोजगारपरक बनाएगा और ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करेगा।

6. प्रवास की समस्या का समाधान

मोहला-मानपुर क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेषकर युवा वर्ग, अन्य राज्यों और शहरों की ओर प्रवास करते हैं। इससे परिवारों में सामाजिक असंतुलन, श्रमशक्ति की कमी और स्थानीय विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। प्रवास की इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर पर्याप्त और स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए जाएँ। इसके लिए कृषि आधारित लघु उद्योगों, वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आधुनिक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत कर स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। यदि स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएँ तो प्रवास की प्रवृत्ति कम होगी और ग्रामीण समाज अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक जीवनयापन कर सकेगा।

7. स्वास्थ्य और सामाजिक विकास

मोहला-मानपुर क्षेत्र के ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संसाधन, दवाइयाँ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी रहती है। इससे ग्रामीणों को सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर समस्याओं तक का समय पर उपचार नहीं मिल पाता और उन्हें शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुदृढ़ स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तो ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार संभव है। इसके साथ ही, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

सामाजिक विकास की दृष्टि से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं और ग्राम संगठनों को सामाजिक जागरूकता अभियानों से जोड़कर ग्रामीण समाज को सामूहिक विकास की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का सशक्तिकरण न केवल ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, बल्कि सतत और समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक ठोस कदम होगा।

8. पर्यटन और संस्कृति का विकास

मोहला-मानपुर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय जीवनशैली से समृद्ध है। यहाँ के हरे-भरे वन, जलप्रपात, पर्वतीय क्षेत्र और जनजातीय लोक-संस्कृति पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं। परंतु पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे जैसे सड़क, आवास, मार्गदर्शन केंद्र और प्रचार-प्रसार की व्यवस्था अभी भी अपर्याप्त है। यदि इस क्षेत्र को ‘इको-टूरिज्म’ और ‘ग्रामीण पर्यटन’ के रूप में विकसित किया जाए तो स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे।

सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से यहाँ की पारंपरिक लोक-कला, नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को संरक्षित और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर सांस्कृतिक मेलों और उत्सवों का आयोजन करके न केवल स्थानीय संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है, बल्कि बाहरी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है। इससे एक ओर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता भी बनी रहेगी। इस प्रकार पर्यटन और संस्कृति का विकास मोहला-मानपुर के ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो सकता है।

15. संदर्भ सूची

1. महालनोबिस, पी. सी. (1955). *Second Five Year Plan Model*. योजना आयोग, भारत सरकार।
2. श्रीनिवास, एम. एन. (1962). *Caste in Modern India and Other Essays*. एशियन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. गाडगिल, डी. आर. (1971). *Economic Problems of India*. एशियन पब्लिशिंग हाउस।

4. सेन, अमर्त्य (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. चेम्बर्स, रॉबर्ट (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. लॉगमैन, लंदन।
6. World Bank (2008). *World Development Report: Agriculture for Development*. Washington D.C.
7. UNDP (2010, 2015). *Human Development Reports*. United Nations Development Programme.
8. रमेश चंद्र (2017). *Doubling Farmers' Income by 2022*. नीति आयोग, भारत सरकार।
9. भारत सरकार (2011). *जनगणना रिपोर्ट 2011*. भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. छत्तीसगढ़ सरकार (2022). *आर्थिक समीक्षा एवं ग्रामीण विकास रिपोर्ट*. रायपुर।
11. Ministry of Rural Development (2020). *Annual Report on MGNREGA and Rural Livelihood Mission*. Government of India।
12. Planning Commission & NITI Aayog (2000–2020). *Five Year Plans and Development Reports*. नई दिल्ली।
13. International Fund for Agricultural Development (IFAD, 2018). *Rural Development Report*. Rome।
14. स्थानीय साक्षात्कार एवं अवलोकन (2024–25) – मोहला–मानपुर विकासखण्ड।

धन्यवाद



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

R
S
E
A
R
C
H
G
A
T
E
W
A
Y

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



A
R
O
G
Y
A
M
O
N
L
I
N
E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER



COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



- BLUE** Calms your Child's Mind & Body
- YELLOW** Promotes Concentration, Stimulates the Memory
- PINK** Evokes Empathy, makes your Child Calm
- RED** Excites and energizes your Child's body
- GREEN** Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE